

CSS और राजकोषीय संघवाद

प्रलम्ब के लिये:

[केंद्र प्रायोजित योजनाएँ \(CSS\)](#), [राजकोषीय संघवाद](#), [अनुच्छेद 282](#), [अनुच्छेद 270 और 275](#), [वित्त आयोग](#), [वित्तियोग अधिनियम](#), [भारत की संघीय निति](#), [योजना आयोग](#), [नीति आयोग](#), [सातवीं अनुसूची](#), [अंतर-राज्य परिषद](#)।

मेन्स के लिये:

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) और उनके कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।

[स्रोत: फाइनेंसियल एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

केंद्र ने पिछले हस्तांतरणों से 1.6 लाख करोड़ रुपए की अप्रयुक्त धनराशि पाए जाने के बाद, वर्ष 2025-26 के लिये राज्यों को [केंद्र प्रायोजित योजनाओं \(CSS\)](#) के लिये व्यय में 91,000 करोड़ रुपए (योजनाओं के लिये बजट अनुमान का 18%) की कटौती की है।

- कई राज्यों ने इस निर्णय को [राजकोषीय संघवाद](#) के विपरीत बताया है और [अनुच्छेद 282](#) की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए हैं।

अनुच्छेद 282 क्या है?

- परिचय: यह संघ और राज्यों दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिये अनुदान देने की अनुमति देता है, भले ही वह उद्देश्य उनके विधायी क्षेत्राधिकार से बाहर हो।
 - कर हस्तांतरण ([अनुच्छेद 270 और 275](#)) के विपरीत, [अनुच्छेद 282](#) के तहत अनुदान विकास के लिये है और [वित्त आयोग \(FC\)](#) की सिफारिशों से बाध्य नहीं है।
 - प्रारंभ में अप्रत्यक्ष आय आकस्मिकताओं के लिये इसका उपयोग किया गया था, तथा बाद की केंद्र सरकारों ने इसका उपयोग CSS को लागू करने के लिये किया।
 - [अनुच्छेद 270 और 275](#) के अनुसार वित्त आयोग संघीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करेगा।
- न्यायिक दृष्टिकोण: [\[2017\] 2 SCR 1000, 2010](#) में, [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने [FC सिफारिशों \(अनुच्छेद 275\)](#) से परे भी, [अनुच्छेद 282](#) के तहत विकास के लिये अनुदान प्रदान करने की केंद्र की शक्ति को बरकरार रखा।
 - संसद की विधायी क्षमता से परे विधियों के लिये भी अनुदान दिया जा सकता है, बशर्ते कि वे सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करती हों।
 - [\[2017\] 2 SCR 1000, 2010](#) का हवाला देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि [भारत की संघीय निति \(CFI\)](#) से व्यय को अधिकृत करने वाले [वित्तियोग अधिनियम](#), [अनुच्छेद 282](#) के तहत अनुदान को कानूनी रूप से उचित ठहराते हैं।

CSS राजकोषीय संघवाद को कैसे चुनौती देता है?

- विकास के लिये CSS वित्तपोषण: [अनुच्छेद 282](#) के तहत संघ या राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिये धन दे सकते हैं, भले ही उनके पास इस पर विधायी अधिकार न हो।
 - [नीति आयोग](#) 2015 (पूर्ववर्ती [योजना आयोग](#) की तरह, जो संवैधानिक दर्जा न होने के बावजूद अनुदानों का मार्गदर्शन करता था), CSS डिजाइन को प्रभावित करना जारी रखता है।
- राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता का कथन: CSS में [निति उपयोग की शर्तें सख्त हैं](#), जिससे राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें अपनाने में लचीलापन सीमित हो जाता है।
 - उदाहरण के लिये, [पोषण अभियान](#) के अंतर्गत राज्य लक्ष्य समूहों या प्रमुख पोषण संकेतकों में परिवर्तन नहीं कर सकते।
- संसाधन-व्यय वित्तपोषण: [15वाँ वित्त आयोग \(2021-26\)](#) में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि केंद्र के पास 63% संसाधन हैं लेकिन इसके द्वारा 38% व्यय किया जाता है, जबकि राज्यों के पास शेष 37% है लेकिन वे 62% व्यय वहन करते हैं।

- इससे राज्यों की **CSS नधियों पर नरिभरता बढ़ जाती है** तथा राज्य-वशिष्ट पहलें सीमिति हो जाती हैं।
- **प्राथमकिता संबंधी मुद्दे:** CSS नधियों के लिये राज्यों को **समतुल्य अनुदान** उपलब्ध कराने की आवश्यकिता होती है, जसिसे इनके सनसाधनों का राज्य-प्राथमकिता वाले क्षेत्रों से इतर अन्य क्षेत्रों में वयव हो जाता है।
- **सहकारी संघवाद के लिये खतरा:** संवधान सभा बहस के दौरान, **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** ने संघ और राज्यों के बीच समान भागीदारी पर ज़ोर दिया था लेकिन वविकाधीन CSS अनुदान पर अत्यधिक नरिभरता से **सहकारी संघवाद** का संवैधानिक अभिप्राय प्रभावति होता है।
 - उदाहरण के लिये, CSS दशिा-नरिदेशों में **केंद्रीय नेतृत्व** को उजागर करने और केंद्रीय नयितरण को मज़बूत करने के लिये **“ब्रांडिंग”** को अनवारिय कया गया है।
- **संघ की नीतियों का वसितार:** राज्यों को नयितरति करने के लिये **राजनीतिक साधन** के रूप में CSS का उपयोग बढ़ता जा रहा है।
 - उदाहरण के लिये, वतित मंत्रालय के वरष **2022 के दशिा-नरिदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वनिविश के इच्छुक राज्यों के लिये 50,000 करोड रुपए का ब्याज मुक्त ऋण** शामिल था, जसिका कई राज्यों ने वरिोध कया था।
- **CSS फंडिंग का प्रसार:** CSS फंड रलीज़ वरष 2014-15 में कुल अंतरण के **7.5% से बढ़कर वरष 2022-23 में 47% हो गया**, जसिसे वतित आयोग द्वारा अनुशंसति हस्तांतरण में कमी आई।
 - **संवधान की सातवीं अनुसूची** के वपिरीत, कई CSS का कार्यक्षेत्र **राज्य सूची** के अंतरगत आने वाले क्षेत्रों में वसितारति है, जसिसे राज्य के अधिकार क्षेत्र में केंद्र का अतिक्रमण होता है।

केन्द्र प्रायोजति योजनाएँ (CSS) क्या हैं?

- **परचिय:** CSS को केंद्र और राज्यों द्वारा **संयुक्त रूप से वतित पोषति** कया जाता है, **राज्यों द्वारा कार्यानवति कया जाता है** और इसके तहत संवधान की **राज्य और समवर्ती सूचियों** के अंतरगत क्षेत्रों को कवर कया जाता है।
 - चूँकि **केंद्र सरकार के पास अधिक वतितीय संसाधन** हैं इसलिये इन योजनाओं से **राज्य सरकारों के प्रयासों को अतरिकित सहायता** मलति है।
 - राज्यों को केंद्रीय सहायता योजनाओं के लिये सभी अंतरण **राज्य की समेकति नधि** के माध्यम से कयि जाते हैं।
- **प्रकार:** CSS को तीन मुख्य श्रेणियों में वभाजति कया गया है :
 - **कोर ऑफ द कोर स्कीम:** ये योजनाएँ सामाजिक समावेशन और संरक्षण के लिये **सर्वाधिक महत्वपूर्ण** हैं। उदाहरण के लिये, **मनरेगा**।
 - **कोर स्कीम:** ये योजनाएँ **कृषि, बुनियादी ढाँचे, शकिषा, स्वास्थ्य और ग्रामीण वकिसा** जैसे **वभिन्नि वकिसात्मक क्षेत्रों पर केंद्रति** हैं।
 - उदाहरणार्थ, **मध्यानह भोजन योजना** (स्कूल पोषण कार्यक्रम), **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** (ग्रामीण सड़कें) आदि।
 - **ऑप्शनल स्कीम:** इसके अंतरगत राज्य अपनी इच्छानुसार योजनाओं का चयन कर सकते हैं।
 - उदाहरण: **सीमा क्षेत्र वकिसा कार्यक्रम** आदि।
- **वतितपोषण स्वरूप:** केंद्र अपने बजट का लगभग **12% CSS को आवंटति करता है**, जसिमें **वभिन्नि केंद्र-राज्य अनुपातों में वतितपोषण** साझा कया जाता है:
 - 60:40 (अधिकांश योजनाएँ)
 - 80:20 (वशिष योजनाएँ)
 - 90:10 (पूर्वोत्तर एवं वशिष श्रेणी राज्यों के लिये)
- **केंद्र प्रायोजति और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के बीच अंतर:**

वशिषता	केंद्र प्रायोजति योजनाएँ (CSS)	केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएँ
कार्यानवयन	राज्य सरकारों द्वारा	केंद्र सरकार द्वारा
वतितपोषण स्रोत	साझा वतितपोषण (केंद्र एवं राज्य)	केंद्र द्वारा पूर्णतः वतितपोषति
उदाहरण	MGNREGA, PMAY , सर्वोच्च भारत मशिन	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मशिन , PM-कसिन

आगे की राह

- **अनुच्छेद 282 पर न्यायिक स्पष्टता:** सर्वोच्च न्यायालय को **यह मूल्यांकन करना चाहयि** कि **CSS से संघीय संतुलन** पर प्रभाव पड़ता है तथा उन वशिष परसिथितियों को स्थापति करना चाहयि जनिके अंतरगत **वविकाधीन अनुदानों** का उपयोग कया जा सकता है।
- **CSS का युक्तकिरण:** **समान CSS को प्रभावी अमब्रेला योजनाओं** में वलिय करने के साथ अप्रभावी योजनाओं को समाप्त करने के क्रम में **नयिमति प्रभाव आकलन** करना चाहयि।
- **वतितपोषण तंत्र की समीक्षा:** राज्यों के वतितीय बोझ को कम करने के क्रम में **नधि-साझाकरण पैटर्न** को संशोधति (वशिष रूप से **सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये**) करना चाहयि और **पछिड़ा क्षेत्र अनुदान नधि (BRGF)** बंद होने के बाद पछिड़े क्षेत्रों के लिये समर्थन को बहाल करना चाहयि।
- **सहकारी संघवाद को मज़बूत करना:** अंतर-राज्य परषिद और नीतिआयोग के माध्यम से नयिमति **केंद्र-राज्य परामर्श** पर ध्यान देना चाहयि तथा राज्यों को **स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार CSS को अनुकूलति करने** में अधिक लचीलापन प्रदान करना चाहयि।

दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में राजकोषीय संघवाद पर केंद्र प्रायोजति योजनाओं (CSS) के प्रभाव की चर्चा कीजयि। अनुच्छेद 282 के तहत वविकाधीन अनुदान, राज्यों

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न: स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, 2017 के संबंध में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

1. यह एक दशक में हमारे देश के प्रत्येक शहर को स्मार्ट सटि के रूप में वकिसति करने के लयि केंद्र-प्रायोजति योजना है ।
2. यह हमारे देश के समक्ष आने वाली कई समस्याओं को हल करने के लयि नई डजिटिल प्रौद्योगिकी नवाचारों की पहचान करने की एक पहल है ।
3. इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन-देन को पूरी तरह से डजिटिल बनाना है ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 3
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: B

??????

प्रश्न: भारत के 14वें वतित्त आयोग की सफिरशिों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थितिमें सुधार करने में कसि प्रकार सक्षम बनाया है? (2021)

प्रश्न: हाल के वर्षों में सहकारी परसिंघवाद की संकल्पना पर अधकिधकि बल दयि जाता रहा है । वदियमान संरचना में मौजूद असुवधिओं के बारे में बताते हुए सहकारी परसिंघवाद कसि सीमा तक इन असुवधिओं का हल नकिल लेगा, इस पर प्रकाश डालें । (2015)